



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 138 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2001/ज्येष्ठ 10, 1923

No. 138]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2001/JYAISTHA 10, 1923

168

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2001

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान) (संशोधन) विनियम, 2001

फा. सं. आई आर डी ए/रेग/5/2001.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 27क, 27ख, 27घ और 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाह समिति के परामर्श से, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान) विनियम, 2000, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम जोगः विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान) (संशोधन) विनियम, 2001 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान) विनियम, 2000 में, विनियम 2 के खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(खक) “आस्ति” से बीमाकर्ता की वे सभी आस्तियां अभिप्रैत हैं जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरण तैयार करना और बीमा कंपनी की सेखा परीक्षा रिपोर्ट) विनियम, 2000 के प्रूरूप ख-ख ठ में दिए गए उसके तुलनपत्र से दर्शित उसका वहन मूल्य हो किन्तु “प्रकीर्ण व्यय” शोषक के अधीन की मर्दें अपवर्जित हैं।

3. विद्यमान विनियम 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:-

### 3. विनिधान का प्रकार

(1) जीवन कारबार : अधिनियम की धारा 27क के स्पष्टीकरण के नियंत्रणों के अनुसार, प्राधिकरण ने यह अवधारित किया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए पैशन कारबार, वार्षिकी कारबार और यूनिट जीवन बीमा कारबार नियंत्रित निधि के भाग नहीं होंगे।

अधिनियम की धारा 27 या 27क पर प्रतिकूल डाले बिना—जीवन बीमा का कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी नियंत्रित निधि को (पैशन और साधारण वार्षिकी और यूनिट जीवन बीमा कारबार में संबंधित निधियों को छोड़कर) निम्नलिखित रीति से विनिहित करेगा और सभी समयों पर विनिहित रखेगा।

क्र.सं.	विनिधान का प्रकार	प्रतिशतता
(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	25%
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (जिनमें ऊपर (i) भी सम्मिलित हैं)	50% अन्यून
(iii)	अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट अनुमोदित विनिधान	
(क)	अवसंरचना और सामाजिक सेक्टर  स्पष्टीकरण : अपेक्षा, अवसंरचना और सामाजिक सेक्टर का इस प्रयोजन के लिए वहीं अर्थ होगा जो क्रमशः, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2000 में है और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर के लिए बीमाकर्ताओं की आधिकारिता) विनियम, 2000 में परिभाषित है।	15% से अन्यून
(ख)	विनियम 5 में यथाविनिर्दिष्ट अधिदर्शित सन्नियमों द्वारा शासित किए जाने वाले अन्य। “अनुमोदित विनिधानों से भिन्न” में विनिधान किसी भी दशा में निधि का 15% से अधिक नहीं हो सकता।	35% से अनधिक

(2) पैशान और साधारण वार्षिकी कारबार : प्रत्येक बीमाकर्ता अपने पैशान कारबार, साधारण वार्षिकी कारबार से संबंधित निधियों को निम्नलिखित रीति से विनिहित करेगा और सभी समर्थों पर विनिहित रखेगा :-

क्र.सं.	विनिधान का प्रकार	प्रतिशतता
(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ,	25% से अन्यून
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियाँ या अन्य प्रतिभूतियाँ (ऊपर (i) को छोड़कर)	40% से अन्यून
(iii)	अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट अनुमोदित विनिधानों में विनिहित किया जाने वाला और विनियम 5 में विनिर्दिष्ट अधिदर्शित/प्रज्ञायुक्त सन्नियम में द्वारा शासित किया जाने वाला अतिरिक्त	60% से अधिक

टिप्पण : इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए कोई भी अनुमोदित विनिधान नहीं किया जाएगा।

(3) ‘यूनिट जीवन बीमा कारबार’-प्रत्येक बीमाकर्ता पालिसीधारक की प्रस्थापना और उसके द्वारा अनुमोदित विनिधान के पैटर्न के अनुसार, यूनिट जीवन बीमा कारबार की अपनी पृथक् निधियों को विनिहित करेगा और सभी समर्थों पर विनिहित रखेगा। यूनिट पालिसियाँ केवल वहाँ प्रस्थापित की जा सकेंगी जहाँ यूनिट ऐसी आस्तियों के प्रवर्गों से संबद्ध होती हैं जो विपणन योग्य और आसानी से वसूली योग्य दोनों, होती हैं। तथापि, विनिधानों के अनुमोदित प्रवर्ग से भिन्न कुल विनिधान किसी भी समय निधि का 25% से अधिक नहीं होगा।

4. विद्यमान विनियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:-

#### 4. विनिधानों का विनियमन

4(1) साधारण कारबार-अधिनियम की धारा 27 या धारा 27ख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना-साधारण बीमा का कारबार करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी कुल आस्तियों को नीचे उल्लिखित रीति में विनिहित करेगा और सभी समर्थों पर विनिहित रखेगा:-

क्र.सं.	विनिधान का प्रकार	प्रतिशतता
(i)	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां	20% से अन्यून
(ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और अन्य गारंटीकृत प्रतिभूतियां जिसमें ऊपर (i) भी हैं	30%
(iii)	आवास और अग्नि शमन उपकरण के लिए राज्य सरकार को आवास ऋण (हुड़को, आवास भवन क्रियाकलापों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंकों द्वारा सम्यक् रूप से प्रत्यायित राष्ट्रीय आवास बैंक या आवास भवन संस्थान, जो सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गारंटीकृत हों या ऐसी स्वतंत्र, सुविख्यात और मान्यताप्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा, जो इस विनियम का अनुपालन करने के लिए भी अहित होंगी, “अ अ” से अन्यून चालू रेटिंग पर कारबाह करते हों, द्वारा जारी बंधपत्रों/डिब्बेचरों को क्रय करने के लिए अभिदान।)	5%
(iv)	अनुसूची 2 में यथा विनिर्दिष्ट अनुमोदित विनिधानों में विनिधान	
(क)	अवसंरचना और सामाजिक सेक्टर	10% से अन्यून
	स्पष्टीकरण : इस प्रयोजन के लिए अपेक्षा, अवसंरचना और सामाजिक सेक्टर का वही अर्थ होगा जो क्रमशः, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2000 में है और जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण और सामाजिक सेक्टर के लिए बीमाकर्ताओं की बाध्यताएं) विनियम, 2000 में परिभाषित है।	
(ख)	विनियम 5 में विनिर्दिष्ट प्रजायुक्त संनियमों द्वारा शासित किए जाने वाले अन्य किन्तु ऐसे कि, “अनुमोदित विनिधानों से भिन्न” विनिधान किसी भी दशा में, आस्तियों का 25% से अधिक नहीं हो सकते।	55% से अनधिक

(2) पुनर्बीमा कारबाह-भारत में पुनर्बीमा कारबाह करने वाला प्रत्येक बीमाकर्ता अपनी कुल आस्तियों को उप-विनियम (1) में नीचे यथा उल्लिखित रीति में तब तक विनिहित करेगा और सभी समयों पर विनिहित रखेगा जब तक प्राधिकरण द्वारा ऐसे समय के लिए इस निमित्त पृथक् विनियम नहीं बनाए जाते हैं।

#### टिप्पण : विनियम 3 और 4 के प्रयोजनों के लिए

- प्रत्येक बीमाकर्ता अवसंरचना सेक्टर और सामाजिक सेक्टर में किए गए विनिधानों के बीच उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगा। इन सेक्टरों के विकास के लिए सरकार या अन्यथा “अ अ” से अन्यून रेटिंग वाले स्वतंत्र, सुविख्यात और मान्यताप्राप्त रेटिंग एजेंसियों द्वारा और अन्यों द्वारा जारी बंधपत्र इस विनियम का पालन करने के लिए अहित होंगे।
- आस्तियों/लिखतों में ऐसे सभी विनिधान, जो बाजार कीमत पढ़ति के अनुसार, रेटिंग किए जाने के लिए समर्थ हों; ऐसी आस्तियों, लिखतों के रेटिंग पर आधारित होंगे।
- रेटिंग स्वतंत्र, सुविख्यात और मान्यताप्राप्त भारतीय और विदेशी रेटिंग ऐसें सी द्वारा होनी चाहिए।
- विनिधान के लिए विचाराधीन आस्तियां/लिखतें उनके वर्तमान रेटिंग के अनुसार, विनिधान श्रेणी के “अ अ” से अन्यून श्रेणी के होंगी। यदि इस श्रेणी के विनिधान, विनिधाता बीमा कंपनी की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं और विनिधाता बीमा कंपनी की विनिधान समिति का इसके बारे में पूर्ण समाधान हो जाता है तो विनिधान समिति के कार्यवृत्त में

विनिधान का प्रकार	विनिधाता कंपनी के लिए सीमा	ऐसे संपूर्ण समूह के, जो विनिधाता कंपनी से संबंधित है, लिए सीमा	ऐसे औद्योगिक सेक्टर के, जो विनिधाता कंपनी से संबंधित है, लिए सीमा
(क) कंपनी के ईक्विटी/ अधिमानी शेयरों में सभी विनिधान	भारतीय बीमा कंपनियों की दशा में: विनिधाता कंपनी की अभिदत्त शेयर पूंजी, खुली आरक्षितियां और डैथप्रत्र/डिवेंचर का, 10% या गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में, बीमाकर्ता की कुल आस्तियों का 10% और जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में, नियंत्रित निधियों का 10% से, जो भी कम हो, किसी भी समय पर अधिक अभिदर्शित न हो।	ऐसी सभी समूह कंपनियों की, जिनमें विनिधान को जिसमें विचाराधीन विनिधान भी सम्प्लित है, बीमाकर्ता द्वारा अभिदर्शित किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, कुल अभिदत्त शेयर पूंजी, खुली आरक्षितियां और डिवेंचरों का 10% या गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में कुल आस्तियों का 10% और जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में, नियंत्रित निधि का 10% से जो भी कम हो, किसी भी समय पर अधिक अभिदर्शित न हो। गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में, कुल आस्तियों के 10% की प्रतिशतता और जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में, नियंत्रित निधि के 10% की प्रतिशतता भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के अध्यधीन प्रत्येक गामले में, 15% तक बढ़ाई जा सकती है।	किसी भी औद्योगिक सेक्टर में बीमाकर्ता द्वारा विनिधान संपूर्ण औद्योगिक सेक्टर के उसके कुल विनिधान अभिदर्शन का 10% से अधिक अभिदर्शित नहीं होगा। औद्योगिक सेक्टर का वर्गीकरण भारतीय आर्थिक मानीटरिंग केन्द्र द्वारा किए गए औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाएगा।
(ख) डिवेंचर (संपरिवर्तनीय/ भागत: संपरिवर्तनीय/ असंपरिवर्तनीय)			
(ग) अस्य/मध्य/दीर्घकालिक ऋण			
(घ) कोई अन्य अनुज्ञाप्रत्र			

**टिप्पण :** बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार, अभिदर्शित सीमाओं के अधीन रहते हुए, ईक्विटी में, जिसमें अधिमानी शेयर विनिधान भी सम्मिलित है, डिवेंचरों के ईक्विटी संपरिवर्तनीय भाग की विनिधान सारणी में यथा उल्लिखित ऊपर अभिदर्शित संनियमों का 50% की अभिदर्शित संनियम सीमा स्थावर संपत्ति में विनिधान को भी लागू होगी।

2. ऊपर सारणी में उल्लिखित अभिदर्शित सीमा के अधीन रहते हुए, बीमाकर्ता, जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में, उसकी कुल नियंत्रित निधियों का 3% से अधिक का या संप्रवर्तक समूहों से संबंधित कंपनियों में गैर-जीवन बीमाकर्ता की दशा में, उसकी कुल आस्तियों का 5% से अधिक का विनिधान नहीं करेगा। इस विनियम के प्रयोजनों के लिए “समूह” का वही अर्थ होगा जो एकाधिकार कथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग अधिनियम, 1969 में है। इस प्रबंग में के सभी विनिधान विनिर्दिष्टः प्राधिकरण को निर्दिष्ट होंगे।

6. (क) विद्यमान विनियम 6 में, सारणी के क्रम संख्या 4 की प्रविष्टि के पश्चात्, क्रम संख्या 5 के रूप में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा :

5	प्ररूप 3ग	ऐसी लिखतों, जो “अअ” या “अअअ” श्रेणी-अनुपालन रिपोर्ट का पालन नहीं करते हैं, संबंधी आक्षेप रिपोर्ट	तिमाही	प्रत्येक तिमाही के अंते के 21 दिन के भीतर	प्रधान अधिकारी/मुख्य (विनिधान)
---	-----------	--	--------	---	--------------------------------

(ख) सारणी में विद्यमान प्रविष्टि क्रम संख्यांक 5 को क्रम संख्यांक 6 के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा।

7. विद्यमान विनियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:-

विनिधान संविभाग को प्रभावित करने वाली असाधारण घटनाओं को रिपोर्ट करने का कर्तव्य

प्रत्येक बीमाकर्ता, उसकी जानकारी में आने वाली किसी भी ऐसी घटना के, जिससे विनिधान संविभाग पर और परिणामतः, पालिसीधारक के फायदों या प्रत्याशाओं की सुरक्षा पर तात्प्रकृति प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव की या संभाव्य प्रभाव की रिपोर्ट तत्काल प्राधिकरण को देगा।

8. विद्यमान विनियम 9 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:-

“9. विनिधान समिति का गठन

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता विनिधान समिति गठित करेगा जिसमें बीमाकर्ता के न्यूनतम दो गैर-कार्यापालक निदेशक, प्रधान अधिकारी, वित्त और विनिधान प्रभाग का मुख्य और जब कभी नियुक्त बीमांकक नियोजित हैं, वहां नियुक्त बीमांकक होंगे। विनिधान समिति द्वारा लिया गया विनिश्चय उचित रूप से अभिलिखित किया जाएगा और प्राधिकरण के अधिकारियों के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) प्रत्येक बीमाकर्ता प्रतिवर्ष विनिधान पालिसी तैयार करेगा और उसे अनुमोदन के लिए निदेशक बोर्ड के समक्ष रखेगा। ऐसी पालिसी विरचित करने में बोर्ड निम्नलिखित विषयों पर,-

(i) परिनिर्धारण से संबंधित मुद्रे, प्रज्ञायुक्त संनियम, अभिदर्शित संनियम, प्रतिभूति ट्रेडिंग में हानि रोक सीमा, सभी विनिधान और बाजार जोखिम का प्रबंधन, असमान आस्ति दायित्वों का प्रबंधन, विनिधान लेखा परीक्षा और विनिधान आंकड़े, आदि तथा बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनिधान) विनियम, 2000 के उपबंधों से संबंधित मुद्रों पर मार्गदर्शन करेगा।

(ii) ऐसी निधियों की संरक्षकता, सुरक्षा और परिनिर्धारण से संगत पालिसीधारकों और शेयरधारकों की निधियों पर पर्याप्त विवरणी सुनिश्चित करने में मार्गदर्शन करेगा।

(iii) बीमाकर्ता की निधियों विनिहित की जाएंगी और ऐसे ईक्विटी शेयरों, अधिमानी शेयरों और लिखतों में निरंतर विनिहित की जाएंगी जिनका वह नीचे विनियम 4 के टिप्पण में निर्दिष्ट रेटिंग पर उपभोग कर सकेगा तथा जो राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों

द्वारा किए गए हों; आस्ति के लिए रेटिंग के अभाव में, बोर्ड स्पष्ट रूप से संनियम अधिकथित करेगा जिनका विनिधान समिति द्वारा अनुसरण किया जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेंगी कि पालिसीधारकों की सुरक्षा और परिनिर्धारण का बीमा किया जाता है।

(3) बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित विनिधान पालिसी विनिधान समिति द्वारा कार्यान्वयन की जाएगी और वह बोर्ड को उसकी गतिविधियों के बारे में कालिक रूप से सूचित करने के लिए रखी जाएगी।

(4) बोर्ड अपनी विनिधान पालिसी और अर्धवार्षिक आधार पर उसके कार्यान्वयन या ऐसे अन्य अंतरालों पर, जो वह विनिश्चित करे, पुनर्विलोकन करेगा और अपनी विद्यमान विनिधान पालिसी में ऐसे उपांतरण करेगा जिन्हें पालिसीधारकों के हितों की संरक्षा और अधिकथित विनिधान के पैटर्न के बारे में-विधि और विनियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए लाना आवश्यक हो।

(5) विनिधान पालिसी या उसके पुनर्विलोकन के, जो बोर्ड द्वारा कालिक रूप से विनिश्चित किए जाएं, व्यौरे उसके विनिश्चय के 30 दिन के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे। प्राधिकरण बीमाकर्ता से समय-समय पर और ऐसी जानकारी, जो वह आवश्यक समझे, और पालिसीधारकों के हितों के लिए बीमाकर्ता को जारी ऐसे निर्देश, जो वह ठीक समझे, मांग सकेगा।"

9. विद्यमान विनियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

#### "10. प्रक्रीण

(1) आस्तियों का मूल्यांकन और विनिधानों का लेखा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणियाँ और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000 के अनुसार होगा।

(2) प्राधिकरण किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी भी बीमाकर्ता के अनुरोध पर या उसके द्वारा किए गए आवेदन पर विनियम (3), (4), (5) और (6) के लागू होने को उपांतरित या परिवर्तित कर सकेगा।"

10. विद्यमान अनुसूची 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

#### "अनुसूची 1

(विनियम 3 देखिए)

जीवन कारबार के लिए अनुमोदित विनिधानों की सूची

अधिनियम की धारा 27क के प्रयोजनों के लिए "अनुमोदित विनिधान" निम्नलिखित रूप में होगा :

(क) अधिनियम की धारा 27क में विनिर्दिष्ट सभी अनुमोदित विनिधान सिवाय निम्नलिखित के,-

(i) अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (1) के खंड (ख);

(ii) अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (1) के खंड (ड) में यथाकथित अन्य देश में स्थित स्थावर संपत्ति पर प्रथम बंधक;

(iii) अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (1) के खंड (ट) में यथाकथित अन्य देश में स्थित स्थावर संपत्ति।

(ख) इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा दी गई शक्ति के अधीन निम्नलिखित विनिधानों को अनुमोदित विनिधानों के रूप में घोषित कर सकेगा-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक की हैसियत से मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी सभी प्रतिभूत उधार, प्रतिभूत डिबेंचर, प्रतिभूत बंधपत्र, अन्य प्रतिभूत ऋण लिखतें, शेयर और अधिमानी शेयर और ऋण लिखतें-बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनिधान पालिसी मार्गदर्शी सिद्धांत, बैंचमार्क और अभिदर्शित संनियम/सीमा।

(ii) बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित संनियमों/सीमाओं के अधीन रहते हुए, बैंक में निक्षेप को (अर्थात् चालू खाता, मांग निक्षेप, निक्षेप की सूचना, निक्षेप प्रमाणपत्र आदि) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त प्रारंभिक व्यौहारी के साथ निक्षेप।

(iii) किसी कंपनी या 'बहुत मजबूत' प्रबर्ग के अंतर्गत सुविष्यात और स्वतंत्र रेटिंग वाली एजेंसी द्वारा या उससे अधिक रेटिंग वाली भारतीय रिजर्व बैंक की हैसियत से मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा जारी वाणिज्यिक कागज-पत्र;

(iv) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी खजाना हुंडियां, भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर-बैंक रिपोज और पुनःमित्तिकाद्य भुगतान।

#### स्पष्टीकरण :

1. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में किए गए अल्प, मध्य या दीर्घकालिक उधार या निक्षेप में कोई विनिधान "अनुमोदित विनिधान" के रूप में नहीं समझा जाएगा।

2. विनियम 3 और 4 को लागू "टिप्पण" में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जाना है।"

विधमान अनुसूची 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

#### अनुसूची 2

(विनियम 4 देखिए)

साभारण कारबार के लिए अनुमोदित विनिधानों की सूची

अधिनियम की धारा 27ख के प्रयोजन के लिए 'अनुमोदित विनिधान', निम्नलिखित रूप में होंगे :-

(क) अधिनियम की धारा 27ख में विनिर्दिष्ट सभी अनुमोदित विनिधान सिवाय निम्नलिखित के

(i) अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (1) के खंड (ख);

(ii) अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (1) के खंड (ठ) में यथाकथित अन्य देश में स्थित स्थावर संपत्ति;

(iii) अधिनियम की धारा 27ख की उपधारा (1) के खंड (झ) में यथाकथित अन्य देश में स्थित स्थावर संपत्ति पर प्रथम बंधक।

(ख) इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण अधिनियम की धारा 27ख की उपधारा (1) के खंड (अ) द्वारा दी गई शक्ति के अधीन निम्नलिखित विनिधानों को अनुमोदित विनिधानों के रूप में घोषित कर सकेगा :

(i) भारतीय रिजर्व बैंक की हैसियत से मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी सभी प्रतिभूत उधार, प्रतिभूत डिबेंचर, प्रतिभूत बंधपत्र, अन्य प्रतिभूत ऋण लिखतें, शेयर और अधिमानी शेयर और ऋण लिखतें-बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित विनिधान पालिसी; मार्गदर्शी सिद्धांत, बैंचमार्क और अभिदर्शित संनियम/सीमा।

(ii) बीमाकर्ता के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित संनियमों/सीमाओं के अधीन रहते हुए, बैंक में निक्षेप को (अर्थात् चालू खाता, मांग निक्षेप, निक्षेप की सूचना, निक्षेप प्रमाणपत्र आदि) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सम्मिलित किया गया है और इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सम्यक् रूप से मान्यताप्राप्त प्रारंभिक व्यौहारी के साथ निक्षेप।

(iii) किसी कंपनी या 'बहुत मजबूत' प्रबर्ग के अधीन सुविष्यात और स्वतंत्र रेटिंग वाली एजेंसी द्वारा या उससे अधिक रेटिंग वाली भारतीय रिजर्व बैंक की हैसियत से मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय वित्तीय संस्था द्वारा जारी वाणिज्यिक कागज-पत्र।

(iv) भारतीय रिवर्ज बैंक द्वारा जारी खजाना हुंडियां, भारतीय रिजर्व बैंक के अन्तर-बैंक रिपोज और पुनःमित्तिकाद्य भुगतान;

#### स्पष्टीकरण :

1. प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में किए गए अल्प, मध्य या दीर्घकालिक उधार या निक्षेप में कोई विनिधान अनुमोदित विनिधान के रूप में नहीं समझा जाएगा।

2. विनियम 3 और 4 को, लागू 'टिप्पण' में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन किया जाना है।

II. विद्यमान अनुसूची 3 को हटा दिया जाएगा।

12. (क) विद्यमान प्ररूप 3क और प्ररूप 3ख के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

प्ररूप 3क

कंपनी का नाम और कोड

विवरण तारीख : ----- को

पेंशन और साधारण वार्षिकी कारबार तथा यूनिट जीवन बीमा कारबार से भिन्न नियंत्रित निधियों के विनिधान का विवरण-अनुपालन रिपोर्ट तिमाही प्रस्तुत की जाने हैं

जीवन कारबार

		नियंत्रित निधि का विनिधान			
क्र.सं.	विनिधान का प्रकार	प्रतिशतता	विनियमों के अनुसार विनिहित रकम	वास्तविक प्रतिशत	बाजार मूल्य या वसूली योग्य मूल्य
(i)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	25%			
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियाँ या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (ऊपर (i) सहित)	50% से अन्यून			
(iii)	अनुमोदित विनिधान				
(क)	अवसंरचना और सामाजिक सेक्टर (i) अवसंरचना सेक्टर (ii) सामाजिक सेक्टर	15% से अन्यून	(i) (ii)		
(ख)	(i) विनियम 5 में विनिर्दिष्ट अभिदर्शित संनियमों द्वारा शासित किए जाने वाले अन्य (ii) उपरोक्त 35% में से, अनुमोदित विनिधानों से भिन्न विनिधान की प्रतिशतता 15% से अधिक नहीं	35% से अनधिक	(i) (ii)		
	कुल विनिधान	100%			

पेंशन कारबार और साधारण वार्षिकी कारबार से संबंधित निधियों के विनिधान का विवरण-अनुपालन रिपोर्ट तिमाही प्रस्तुत की जानी है।

#### पेंशन कारबार, साधारण वार्षिकी कारबार

क्र.सं.	विनिधान का प्रकार	आस्तियों का विनिधान			
		प्रतिशतता	विनियमों के अनुसार विनिहित रकम	वास्तविक प्रतिशत	बाजार मूल्य या वसूली योग्य मूल्य
(i)	सरकारी प्रतिभूतियां,	20% से अन्यून			
(ii)	सरकारी प्रतिभूतियां या अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (उपरोक्त (क) सहित)	40% से अन्यून			
(iii)	अनुमोदित विनिधानों में विनिहित किया जाने वाला विनिधान अतिशेष,	60% से अनधिक			
	कुल विनिधान	100%			

“यूनिट जीवन बीमा कारबार” के विनिधान का विवरण-अनुपालन रिपोर्ट तिमाही प्रस्तुत की जानी है।

#### जीवन बीमा कारबार

क्र.सं.	विनिधान का प्रकार	आस्तियों का विनिधान			
		प्रतिशतता	विनियमों के अनुसार विनिहित रकम	वास्तविक प्रतिशत	बाजार मूल्य या वसूली योग्य मूल्य
(i)	अनुमोदित विनिधान	75% से अन्यून			
(ii)	अननुमोदित विनिधान	25% से अनधिक			
	कुल विनिधान	100%			

#### प्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

तारीख -----

हस्ताक्षर -----

पूरा नाम और पदनाम

प्ररूप 3 ख

कंपनी का नाम और कोड

विवरण तारीख ----- को

कुल आस्तियों के विनिधान का विवरण-अनुपालन रिपोर्ट तिमाही प्रस्तुत की जानी है।

साधारण कारबार

क्र.सं.	विनिधान का प्रकार	आस्तियों का विनिधान			
		प्रतिशतता	विनियमों के अनुसार विनिहित रकम	वास्तविक प्रतिशत	बाजार मूल्य या वसूली योग्य मूल्य
(i)	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ,	20% से अन्यून			
(ii)	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ और अन्य गारंटीकृत प्रतिभूतियाँ ऊपर (क) सहित,	30% से अन्यून			
(iii)	आवास और अग्नि शमन उपकरण के लिए राज्य सरकार को आवास और उधार	5% से अन्यून			
(iv)	अनुमोदित विनिधान				
(क)	अवसंरचना और सामाजिक सेक्टर (i) अवसंरचना सेक्टर (ii) सामाजिक सेक्टर	10% से अन्यून	(i) (ii)		
(ख)	(i) विनियम 5 में विनिर्दिष्ट अभिदर्शित संनियमों द्वारा शासित किए जाने वाले अन्य (ii) ऊपर 55% में से, अनुमोदित विनिधान से भिन्न विनिधानों में 25% से अधिक नहीं	55% से अनधिक	(i) (ii)		
	कुल विनिधान	100%			

#### प्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

तारीख -----

हस्ताक्षर -----

पूरा नाम और पदनाम

13. प्रतिस्थापित प्ररूप 3ख के पश्चात्, निम्नलिखित नया प्ररूप 3ग अंतःस्थापित किया जाएगा :

प्ररूप 3ग

कंपनी का नाम और कोड

विवरण की तारीख ----- को

I. दरगम्य लिखत, जो “अअ” श्रेणी का अनुपालन नहीं करती हैं, संबंधी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण लिखतों की, जो “अअअ” श्रेणी का अनुपाल नहीं करते हैं, दशा में आक्षेप रिपोर्ट-अनुपालन रिपोर्ट तिमाही प्रस्तुत की जानी है।

(क) जीवन कारबार

क्र.सं.	लिखत का नाम	लिखत की रेटिंग करने वाला संस्थान	लिखत की रेटिंग श्रेणी	लिखत में विनिहित रकम	विनिधान समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

(ख) पेंशन और साधारण वार्षिकी कारबार

क्र.सं.	लिखत का नाम	लिखत की रेटिंग करने वाला संस्थान	लिखत की रेटिंग श्रेणी	लिखत में विनिहित रकम	विनिधान समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

(ग) यूनिट जीवन बीमा कारबार

क्र.सं.	लिखत का नाम	लिखत की रेटिंग करने वाला संस्थान	लिखत की रेटिंग श्रेणी	लिखत में विनिहित रकम	विनिधान समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

(घ) साधारण कारबार

क्र.सं.	लिखत का नाम	लिखत की रेटिंग करने वाला संस्थान	लिखत की रेटिंग श्रेणी	लिखत में विनिहित रकम	विनिधान समिति द्वारा अनुमोदन की तारीख और उसके कारण

### प्रमाणित

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

तारीख -----

हस्ताक्षर -----

पूरा नाम और पदनाम

## 14. विद्यमान प्ररूप 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :-

प्ररूप 4

कंपनी का नाम और कोड

विवरण की तारीख ----- को

अभिदर्शित संनियम—अनुपालन रिपोर्ट वर्ष में प्रस्तुत की जानी है।

विनिधान के प्रकार में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- क) कंपनी के ईक्विटी/अधिभानी शेयरों में सभी विनिधान
- ख) डिबैंचर (संपरिवर्तनीय-भागत; संपरिवर्तनीय/असंपरिवर्तनीय)
- ग) अल्प/मध्य/दीर्घकालिक उधार
- घ) अधिनियम/विनियम के अनुसार, कोई अन्य अनुजाग्राहक विनिधान

## अभिदर्शित संनियम

क्र.सं.	विनियमों के अनुसार संनियम	क्या अभिदर्शित संनियमों का पालन किया गया है या नहीं	टिप्पणियां
1.	<p><b>विनिधाता कंपनी के लिए संनियम</b></p> <p>भारतीय बीमा कंपनियों की दशा में :</p> <p>किसी भी समय विनिधाता कंपनी की अभिदत्त शेयर पूँजी, खुली आरक्षितियां और डिबैंचर/बंधपत्र 10% से अधिक या गैर-जीवन बीमाकर्ता की दशा में, बीमाकर्ता की कुल आस्ति 10% से अधिक या जीवन बीमाकर्ता की दशा में, नियंत्रित निधि 10% से अधिक, इनमें से जो भी कम हो, अभिदर्शित न हो।</p>		
	<p><b>विद्यमान बीमाकर्ता की दशा में :</b></p> <p>किसी भी समय विनिधाता कंपनी की अभिदत्त शेयर पूँजी, डिबैंचर/बंधपत्र 20% से अधिक या जीवन बीमाकर्ता की नियंत्रित निधि का 5% से अधिक या साधारण बीमाकर्ता की कुल आस्तियों का 10% से अधिक अभिदर्शित न हो।</p>		
	<p>बीमा अधिनियम, 1038 के अनुसार, अभिदर्शित सीमा के अधीन रहते हुए, ईक्विटी में, जिसमें अधिभानी शेयर भी है, विनिधान, डिबैंचरों के ईक्विटी संपरिवर्तनीय भाग में विनिधान ऊपर अभिदर्शित संनियमों का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। 50% की ऐसे ही अभिदर्शित सीमा स्थावर संपत्ति में विनिधान को भी लागू होगी।</p>		

		<p>ऊपर सारणी में उल्लिखित अभिदर्शित सीमा के अधीन रहते हुए, बीमाकर्ता को जीवन बीमाकर्ता की दशा में, अपनी कुल नियंत्रित निधि का 5% से अधिक या संप्रबद्धतक समूहों से संबंधित कंपनियों में गैर-जीवन बीमाकर्ता की दशा में, अपनी कुल आस्तियों का 5% से अधिक विनिधान नहीं करना होगा। इस विनियम के प्रयोजन के लिए, “समूह” का वही अर्थ होगा जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग अधिनियम, 1969 में है। इस प्रवर्ग के सभी विनिधान विनिर्दिष्टः प्राधिकरण को निर्दिष्ट होंगे।</p>	
2.	ऐसे संपूर्ण समूह के, जो विनिधाता कंपनी से संबंधित है, लिए सीमा	<p>किसी भी समय ऐसे सभी समूह कंपनियों की, जिसमें विनिधान को, जिनमें विचाराधीन विनिधान भी सम्मिलित हैं किया गया है या किए जाने का प्रस्ताव है, को बीमाकर्ता द्वारा अभिदर्शित, कुल अभिदत्त शेर्यर पूँजी, खुली आरक्षितियों और डिबैंचरों का 10% से अधिक या गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में, कुल आस्तियों का 10% से अधिक अभिदर्शित न हो और जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में-नियंत्रित निधि का 10% से अधिक अभिदर्शित न हो, इनमें से जो भी कम हो। गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में कुल आस्तियों के 10% की की प्रतिशतता और जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में, नियंत्रित निधि के 10% की प्रतिशतता भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण के विनिर्दिष्ट अनुमोदन के अध्यधीन प्रत्येक मामले में 15% तक बढ़ाई जा सकती है। “इनमें से जो भी कम हो” छंड निरंतर लागू होगा।</p>	
		<p>बीमा विनियामक, 1938 के अनुसार, अभिदर्शित सीमाओं के अधीन रहते हुए, ईकियटी में, जिसमें अधिमानी शेर्यर भी सम्मिलित हैं, विनिधान, डिबैंचरों के ईकियटी संपरिवर्तनीय भाग में विनिधान ऊपर अभिदर्शित संनियमों का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार की 50% की अभिदर्शित संनियम सीमा स्थावर संपत्ति में विनिधान को भी लागू होगी।</p>	
		<p>ऊपर सारणी में उल्लिखित अभिदर्शित सीमा के अधीन रहते हुए, बीमाकर्ता, जीवन बीमाकर्ताओं की दशा में, उसकी कुल नियंत्रित निधियों का 5% से अधिक का या संप्रबद्धतक समूहों से संबंधित कंपनियों में गैर-जीवन बीमाकर्ता की दशा में, उसकी कुल आस्तियों का 5% से अधिक का विनिधान नहीं करेगा। इस विनियम के प्रयोजन के लिए, “समूह” का वही अर्थ होगा जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग अधिनियम, 1969 में है। इस प्रवर्ग में के सभी विनिधान विनिर्दिष्टः प्राधिकरण को निर्दिष्ट होंगे।</p>	

3.	उस औद्योगिक सेक्टर के लिए सीमा, जो विनिधाता कंपनी से संबंधित है।	किसी औद्योगिक सेक्टर में बीमाकर्ता द्वारा विनिधान संपूर्ण औद्योगिक सेक्टर के लिए उसके कुल अभिदर्शित विनिधान का 10% से अधिक नहीं होगा। ( औद्योगिक सेक्टर का वर्गीकरण भारतीय आर्थिक मानीटरिंग केन्द्र द्वारा किए गए औद्योगिक वर्गीकरण के आधार पर किया जाना है।)		
		बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार, अभिदर्शित सीमा के अधीन रहते हुए, ईक्षिटी में, जिसमें अधिमानी शेयर भी सम्मिलित हैं, विनिधान, डिबैंचरों के ईक्षिटी संपरिवर्तनीय भाग में विनिधान ऊपर अभिदर्शित संनियमों का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार 50% की अभिदर्शित संनियम सीमा स्थावर संपत्ति में विनिधान को भी लागू होगी।		

## प्रमाणन

प्रमाणित किया जाता है कि इसमें दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और उसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

तारीख -----

हस्ताक्षर -----

पूरा नाम और पदनाम

एन. रंगाधारी, अध्यक्ष  
[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/161/2001]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st May, 2001

**F.No. IRDA/Reg/5/2001.** - In exercise of the powers conferred by sections 27A, 27B, 27D and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations to amend the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, namely:-

- 1 (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) (Amendment) Regulations, 2001.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  
- 2 In the Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000, -

After Clause (b) of Regulation 2, the following clause shall be added:-

“(ba) ‘Assets’ means all the assets of insurer, at their carrying value, shown in his Balance Sheet drawn in Form B-BL of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditors’ Report of Insurance Companies) Regulations, 2000, but excluding items under the head ‘Miscellaneous Expenditure’”

- 3 For the existing regulation 3, the following shall be substituted.-

**“3. Regulation of Investments**

(1) Life Business: In terms of explanation in Section 27 A of the Act, the Authority has determined that assets relating to Pension business, Annuity business and Linked Life Insurance business shall not form part of the Controlled Fund for the purpose of that section.

Without prejudice to Section 27 or Section 27A of the Act. - Every insurer carrying on the business of life insurance shall invest and at all times keep invested his controlled fund (other than funds relating to pension and general annuity business and unit linked life insurance business) in the following manner:

S.No	Type of Investment	Percentage
i)	Government Securities	25%
ii)	Government Securities or other approved Securities (including (i) above)	Not less than 50%

iii)	<b>Approved Investments as specified in Schedule I</b>	
a)	<b>Infrastructure and Social Sector</b>  Explanation: For the purpose of this requirement, Infrastructure and Social Sector shall have the meaning as given in regulation 2(h) of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 and as defined in the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural and Social Sector) Regulations, 2000 respectively.	Not less than 15%
b)	Others to be governed by Exposure norms as specified in regulation 5. Investment in "other than approved Investments" can in no case exceed 15% of the fund	Not exceeding 35%

(2) **'Pension and General Annuity Business'**: Every insurer shall invest and at all times keep invested funds belonging to his Pension Business, General Annuity Business in the following manner:-

Sl.No.	Type of Investment	Percentage
(i)	Government Securities, being not less than	20%
(ii)	Government Securities or other approved securities (inclusive (I) above, being not less than)	40%
(iii)	Balance to be invested in Approved Investments as specified in Schedule I and to be governed by Exposure/Prudential Norms specified in Regulation 5	Not exceeding 60%

Note : For the purposes of this sub-regulation no unapproved investments shall be made.

(3) **'Unit Linked Life Insurance Business'**: Every insurer shall invest and at all times keep invested his segregated fund of unit linked life insurance business as per pattern of investment offered to and approved by the policyholders. Unit Linked policies may only be offered where the units are linked to categories of assets which are both marketable and easily realizable. However the total investment in other than approved category of investments shall at no time exceed 25% of the fund.

4. For the existing regulation 4, the following shall be substituted:-

#### **“4. Regulation of Investments”**

4(1) **General Business**: Without prejudice to Section 27 or Section 27B of the Act, - Every insurer carrying on the business of general insurance shall invest and at all times keep invested his total assets in the manner set out below:

S.No	Type of Investment	Percentage
i)	Central Government Securities being not less than	20%
ii)	State Government securities and other Guaranteed Securities including (i) above being not less than	30%
iii)	Housing and Loans to State Government for Housing And Fire Fighting equipment, being not less than, (Subscription to/purchase of Bonds/debentures issued by HUDCO, National Housing Bank or House building institutions duly accredited by National Housing Banks, for house building activities, duly guaranteed by Government or carrying current rating of not less than 'AA' by independent, reputed and recognised rating	5%

	agencies would also qualify for compliance of this regulation.)	
iv)	Investments in Approved Investments as specified in Schedule II	
a)	Infrastructure and Social Sector	Not less than 10%

**Explanation:**

For the purpose of this requirement, Infrastructure and Social Sector shall have the meaning as given in regulation 2(h) of Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000 and as defined in the Insurance Regulatory and Development Authority (Obligations of Insurers to Rural and Social Sector) Regulations, 2000 respectively.

b)	Others to be governed by Exposure Norms specified in regulation 5 so however that investment in "other than approved investments" can in no case exceed 25% of the assets.	Not exceeding 55%
----	--	-------------------

(2)Reinsurance Business: Every reinsurer carrying on reinsurance business in India shall invest and at all times keep invested his total assets in the same manner as set out in sub-regulation (1), until such time separate regulations in this behalf are made by the Authority.

**Note : For the purpose of the regulations 3 and 4:**

1. Every insurer shall endeavor to maintain a proper balance between the investments made in infrastructure sector and those in the social sector. Bonds issued for development of these sectors, duly guaranteed by Government or otherwise rated not less than "AA" by independent, reputed and recognised rating agencies, issued by others would qualify for compliance of this regulation.
2. All investment in assets/ instruments, which are capable of being rated as per market practice, be based on rating of such assets/ instruments.
3. The rating should be by an independent, reputed and recognised Indian or foreign rating agency.
4. The assets/ instruments under consideration for investment, shall be of a grade not less than "AA" of investment grade as per their current rating. In case Investments of this grade are not available to meet the investment requirements of the investing insurance company and investment committee of the investing insurance company is fully satisfied about the same, then, for the reasons to be recorded in the investment committee's minutes, the investment committee may approve investment in instruments carrying current rating of not less than +A. Investments in the +A to be kept to the minimum.
5. The rating of Debt Instruments issued by all India financial institutions recognised as such by RBI may be of 'AAA' or equivalent rating. In case investment of this grade are not available to meet the requirements of the investing insurance company and investment committee of the investing insurance company is fully satisfied about the same, then, for the reasons to be recorded in the investment committee's minutes, the investment committee may approve investments in instruments carrying current rating of not less than 'AA' or equivalent as rated by an independent, reputed and recognised Indian or foreign rating agency.
6. No investment shall be made in an asset/ instrument, which is capable of being rated as per market practice but has not been rated.
7. Investments in equity shares listed on a recognised stock exchange should be made in actively traded and liquid instruments viz., its trading volume does not fall below ten thousand units in any trading session during the last 12 months or trading value of which exceeds Rs. 10 lacs in any trading session during last 12 months."

5. For the existing regulation 5 the following shall be substituted:-

**5. EXPOSURE/ PRUDENTIAL NORMS**

Without prejudice to anything contained in sections 27A and 27B of the Act, every insurer shall limit his investments based on the following exposure norms:

Type of Investment	Limit for Investee Company	Limit for the entire group to which the Investee Company belongs	Limit for the Industry Sector to which the Investee Company belongs
(a) All investments in Equity / Preference Shares of the Company (b) Debentures (Convertible / partly convertible/non-convertible) (c) Short/ Medium/ Long term loans (d) Any other permitted investments as per the Act/Regulation	In the case of Indian Insurance Companies: Exposure at any point of time not to exceed 10% of the subscribed share capital, free reserves and debentures of all the group companies in which investments including investments under considerations, have been or proposed to be made by the insurer or the 10% of the total assets in case of Non-Life Insurers and 10% of the Controlled Funds in case of Life Insurers, whichever is less.  <u>In the case of existing insurers:</u> The limits mentioned above as applicable to the Indian Insurance Companies, shall stand modified as under:- a) exposure at any point of time not to exceed 20% of the subscribed share capital, debentures/bonds of the investee company or 5% of the Controlled funds of the life insurer or 10% of the general insurers total assets	Exposure at any point of time not to exceed 10% of the aggregate subscribed share capital, free reserves and debentures of all the group companies in which investments including investments under considerations, have been or proposed to be made by the insurer or the 10% of the total assets in case of Non-Life Insurers and 10% of the Controlled Funds in case of Life Insurers whichever is less. The percentage of 10% of the total assets in the case on Non-Life insurers and 10% of the Controlled Fund in case of Life insurers can be raised to 15% in each case subject to specific approval of IRDA.	Investment by the insurer in any industrial sector would not exceed 10% of its total investment exposure to the industrial sector as a whole. (Classification of Industrial sector to be done on the lines of classification in Industries done by CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy)

**Notes**

1. Subject to exposure limits as per Insurance Act, 1938, investment in equity including preference shares, investment in equity convertible part of debentures should not exceed 50% of the above exposure norms as mentioned in the table. A similar 50% of exposure norms limit would also apply to investment in immovable property.
2. Subject to exposure limits mentioned in the table above, an Insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its Controlled funds in the case of a life insurer or 5% in aggregate of its assets in the case of non-life insurer in the companies belonging to the promoters' groups. For the purposes of this regulation "group" will have the same meaning as in the MRTP Act, 1969. All investments in this category would specifically be referred to the Authority.

6(a) In the existing regulation 6, after the entry at serial number 4 of the table, the following shall be inserted as serial number 5.

"

5	Form 3C	Exception Report on instruments not complying with "AA" or "AAA" grade – Compliance Report	Quarterly	Within 21 days of the end of each quarter	Principal Officer/Chief (Investment)
---	---------	--	-----------	---	--------------------------------------

(b) The existing entry in the table at serial number 5 shall be re-numbered as serial number 6.

7. For the existing regulation 8, the following shall be substituted:-

**8. Duty to Report extraordinary events affecting the investment portfolio**

Every insurer shall report to the Authority forthwith, the effect or the probable effect of any event coming to his knowledge, which could have material adverse impact on the investment portfolio and consequently on the security of policyholder benefits or expectations.

8. For the existing regulation 9, the following shall be substituted:-

**"9. Constitution of Investment Committee**

(1) Every insurer shall constitute an Investment Committee which shall consist of a minimum of two non-executive directors of the Insurer, the Principal Officer, Chiefs of Finance and Investment divisions, and wherever appointed actuary is employed, the Appointed Actuary. The decisions taken by the Investment Committee shall be properly recorded and be open to inspection by the officers of the Authority.

(2) Every insurer shall draw up annually an Investment Policy and place the same before its Board of Directors for its approval. In framing such a policy, the Board will be guided by

- i) issues relating to liquidity, prudential norms, exposure limits, stop loss limits in securities trading, management of all investment & market risks, management of assets liabilities mismatch, investment audits and investment statistics, etc. and the provisions of the Insurance Act, 1938 and Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000.
- ii) ensuring an adequate return on Policyholders & Shareholders funds consistent with the protection, safety and liquidity of such funds.
- iii) the funds of the insurer shall be invested and continued to be invested in equity shares, preference shares and instruments which enjoy a rating referred to in note below regulation 4 and made by a national/international agency; in the absence of a rating for an asset, the Board shall lay down clearly the norms that will be followed by the investment committee which will ensure that the safety and liquidity of the policyholders' funds are assured.

(3) The investment policy as approved by the Board will be implemented by the investment committee, which shall keep the Board informed periodically about its activities.

(4) The Board shall review its investment policy and its implementation on an half-yearly basis or at such short intervals as it may decide and make such modifications in its existing investment policy as are necessary to bring them in tune with the requirements of law and regulations - in regard to protection of policyholders' interest and pattern of investment laid down.

(5) The details of the Investment Policy or its review as periodically decided by the Board shall be submitted to the Authority within 30 days of its decision thereto. The Authority may call for further information from time to time from the insurer as it deems necessary and in the interest of policyholders issue such directions to the insurers as it thinks fit. "

9. For the existing regulation 10, the following shall be substituted:-

**"10 Miscellaneous**

(1) Valuation of Assets and Accounting of Investments shall be as per the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2000.

(2) The Authority may, by any general or special order, modify or change the application of regulations (3), (4), (5) and (6) to any insurer either on its own or on an application made to it."

10. For the existing Schedule I, the following shall be substituted:-

"

**Schedule I**

(See Regulation 3)

**List of approved Investments for life business**

'Approved Investments' for the purposes of section 27A of the Act shall be as follows:

- (a) all approved investments specified in section 27A of the Act except
  - (i) clause (b) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
  - (ii) first mortgages on immovable property situated in other country as stated in clause (m) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
  - (iii) immovable property situated in other country as stated in clause (n) of sub-section (1) of section 27A of the Act.
- (b) In addition the authority under powers given vide clause (s) of sub-section (1) of section 27A of the Act declares the following investments as approved investments:
  - (i) All secured loans, secured debentures, secured bonds, other secured debt instruments, shares and preference shares and debt instruments issued by all India Financial Institutions recognised as such by Reserve Bank of India – investments to be made in terms of investment policy guidelines, benchmarks and exposure norms/ limits approved by the Board of Directors of the insurer.
  - (ii) Subject to norms/ limits approved by the Board of Directors of the insurers deposits with banks (e.g. in Current account, call deposits, notice deposits, certificate of deposits etc.) included for the time being in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and deposits with Primary Dealers duly recognised by Reserve Bank of India as such.
  - (iii) Commercial papers issued by a company or all India Financial Institution recognised as such by Reserve Bank of India having a rating by a reputed and independent rating agency under the category of 'very strong' or more;
  - (iv) Treasury Bills issued by RBI, Inter-Bank Repos of RBI and Bills Rediscounting.

Explanation :-

1. Any investment in the short or medium or long-term loans or deposits with private limited companies shall not be treated as 'approved investments'.
2. All conditions mentioned in the 'note' applicable to regulations 3 and 4 are to be complied with."

For the existing schedule II, the following shall be substituted:-

"

**Schedule II**

(See Regulation 4)

**List of approved investments for general business**

'Approved Investments' for the purpose of section 27B of the Act shall be as follows:

- (a) All approved investments specified in section 27B of the Act except
  - (i) clause (b) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
  - (ii) Immovable property situated in other country as stated in clause (n) of sub-section (1) of section 27A of the Act;
  - (iii) First mortgages on immovable property situated in other country as stated in clause (i) of sub-section (1) of section 27B of the Act.
- (b) In addition the authority under powers given vide clause (j) of sub-section (1) of section 27B of the Act declares the following investments as approved investments:
  - (i) All secured loans, secured debentures, secured bonds, other secured debt instruments, shares and preference shares and debt instruments issued by all India Financial Institutions recognised as such by Reserve Bank of India – investments to be made in terms of investment policy guidelines, benchmarks and exposure norms/ limits approved by the Board of Directors of an insurer.
  - (ii) Subject to norms/ limits approved by the Board of Directors of the insurers deposits with banks (e.g., in current account, call deposits, notice deposits, term deposits, certificate of deposits etc.) included for the time being in the Second Schedule to Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and deposits with Primary Dealers duly recognised by Reserve Bank of India as such.
  - (iii) Commercial papers issued by a company or all India Financial Institution recognised as such by Reserve Bank of India having a 'very strong' or more rating by a reputed and independent rating agency;

(iv) Treasury Bills issued by RBI, Inter Bank Repos of RBI and Bills Rediscounting;

Explanation :-

1. Any investment in the short or medium or long-term loans or deposits with private limited companies shall not be treated as 'approved investments'.

2. All conditions mentioned in the 'note' applicable to regulations 3 and 4 are to be complied with."

11. The existing Schedule III shall be deleted.

12. (a) The existing Form 3A and Form 3B shall be substituted with the following:-

Form: 3 A

Company Name and Code:

Statement Date: As at .....

Statement of Investment of Controlled Funds other than funds relating to pension and general annuity business and unit linked life insurance business - Compliance Report to be submitted: Quarterly

**Life Business**

INVESTMENT OF CONTROLLED FUND					
S.No.	Type of Investment	Percentage	Amount Invested as per regulations	Actual %	Market Value or Realisable Value
i)	Government Securities	25%			
ii)	Government Securities or other approved securities (including (I) above)	Not less than 50%			
iii)	Approved Investments				
a)	Infrastructure and Social Sector i) Infrastructure Sector ii) Social Sector	Not less than 15%			
b)	i) Others to be governed by Exposure norms specified in regulation 5 ii) Out of the above 35%, percentage of investment in 'Other than Approved Investments' not to exceed 15%	Not exceeding 35%	i) ii)		
	Total Investments	100%			

Statement of Investment of Funds belonging to pension business and general annuity business - Compliance Report to be submitted Quarterly  
Pension Business, General Annuity Business

INVESTMENT OF ASSETS					
S.No.	Type of Investment	Percentage	Amount Invested as per regulations	Actual %	Market Value or Realisable Value
i)	Government Securities being not less than	20%			
ii)	Government Securities or other approved securities (including (a) above) being not less than	40%			
iii)	Balance Investments to be invested in Approved Investments not exceeding	60%			
	Total Investments	100%			

**Statement of Investment of "Unit Linked Life Insurance Business" - Compliance Report to be submitted Quarterly**

**Linked Life Insurance Business**

<b>INVESTMENT OF ASSETS</b>					
S.No.	Type of Investment	Percentage	Amount Invested as per regulations	Actual %	Market Value or Realisable Value
i)	Approved Investment	Not less than 75%			
ii)	Unapproved Investments	Not more than 25%			
	<b>Total Investments</b>	<b>100%</b>			

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Full Name & Designation

Form: 3 B

Company Name and Code:

Statement Date: As at .....

**Statement of Investment of Total Assets - Compliance Report to be submitted Quarterly**

**General Business**

<b>INVESTMENT OF TOTAL ASSETS</b>					
S.No.	Type of Investment	Percentage	Amount Invested as per regulations	Actual %	Market Value or Realisable Value
i)	Central Government Securities being not less than	20%			
ii)	State Government Securities and other Guaranteed securities including a) above being not less than	30%			
iii)	Housing and Loans to State Govt. for Housing and Fire Fighting Equipment being not less than	5%			
iv)	Approved Investments				
a)	Infrastructure and Social Sector	Not less than			
	i) Infrastructure Sector	10%	i)		
	ii) Social Sector		ii)		
b)	i) Others to be governed by Exposure Norms specified in regulation 5	Not exceeding	i)		
	ii) Out of the above 55%, investments in other than Approved Investments not to exceed 25%	55%	ii)		
	<b>Total Investments</b>	<b>100%</b>			

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Full Name & Designation

13. After the substituted Form 3B the following new Form 3C shall be inserted.

“

**Form: 3 C**

**Company Name and Code:**

**Statement Date:** As at .....

I) Exception Report on Instruments capable of being rated and not complying with “AA” grade and in case of debt instruments issued by All India Financial Institutions not complying with “AAA” grade - Compliance Report to be submitted Quarterly

**A) Life Business**

S. No	Name of Instrument	Institution Rating the Instrument	Rating Grade of Instrument	Amount Invested in the instrument	Dt. of approval by the Investment Committee and the reasons thereof

**B) Pension and General Annuity Business**

S. No	Name of Instrument	Institution Rating the Instrument	Rating Grade of Instrument	Amount Invested in the instrument	Dt. of approval by the Investment Committee and the reasons thereof

**C) Unit Linked Life Insurance Business**

S. No	Name of Instrument	Institution Rating the Instrument	Rating Grade of Instrument	Amount Invested in the instrument	Dt. of approval by the Investment Committee and the reasons thereof

**D) General Business**

S. No	Name of Instrument	Institution Rating the Instrument	Rating Grade of Instrument	Amount Invested in the instrument	Dt. of approval by the Investment Committee and the reasons thereof

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

Full Name & Designation

“

14. For the existing Form 4, the following shall be substituted :-

“

**Form: 4**

**Company Name and Code:**

**Statement Date:** As at .....

**Exposure Norms - Compliance Report to be submitted Yearly**

**Type of Investment includes:**

- (a) All investments in Equity / Preference Shares of the Company
- (b) Debentures (Convertible / partly convertible/non-convertible)
- (c) Short/ Medium/ Long term loans
- (d) Any other permitted investments as per the Act/Regulation

## Exposure Norms

S. No		Norms as per regulations	Whether Exposure Norms have been observed or not	Remarks
I	Limit for Investee Company	<p><u>In the case of Indian Insurance Companies:</u> Exposure at any point of time not to exceed 10% of the subscribed share capital, free reserves and debentures/bonds of the investee company or the 10% of the Insurer's total assets in case of non-life insurers and 10% of the Controlled funds in case of Life insurers, whichever is less.</p> <p><u>In the case of existing insurers:</u> Exposure at any point of time not to exceed 20% of the subscribed share capital, debentures/ bonds of the investee company or 5% of the Controlled funds of the life insurer or 10% of the general insurers total assets.</p> <p>Subject to exposure limits as per Insurance Act, 1938, investment in equity including preference shares, investment in equity convertible part of debentures should not exceed 50% of the above exposure norms. A similar 50% of exposure norms limit would also apply to investment in immovable property.</p> <p>Subject to exposure limits mentioned in the table above, an Insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its Controlled funds in the case of a life insurer or 5% in aggregate of its assets in the case of non-life insurer in the companies belonging to the promoters' groups. For the purposes of this regulation "group" will have the same meaning as in the MRTP Act, 1969. All investments in this category would specifically be referred to the Authority.</p>		
II	Limit for the entire group to which investee company belongs	<p>Exposure at any point of time not to exceed 10% of the aggregate subscribed share capital, free reserves and debentures of all the group companies in which the investments including investments under considerations, have been or proposed to be made by the insurer or the 10% of the total assets in case of Non-Life Insurers and 10% of the Controlled Funds in case of Life Insurers whichever is less. The percentage of 10% of the total assets in the case on Non-Life insurers and 10% of the Controlled Fund in case of Life insurers can be raised to 15% in each case subject to specific approval of IRDA. The clause "whichever is less" will continue to apply.</p> <p>Subject to exposure limits as per Insurance Act, 1938, investment in equity including preference shares, investment in equity convertible part of debentures should not exceed 50% of the above exposure norms. A similar 50% of exposure norms limit would also apply to investment in immovable property.</p> <p>Subject to exposure limits mentioned in the table above, an Insurer shall not have investments of more than 5% in aggregate of its Controlled funds in the case of a life insurer or 5% in aggregate of its assets in the case of non-life insurer in the companies belonging to the promoters' groups. For the purposes of this regulation "group" will have the same meaning as in the MRTP Act, 1969. All investments in this category would specifically be referred to the Authority.</p>		

III	Limit for the industry sector to which the investee company belongs	<p>Investment by the insurer in any industrial sector would not exceed 10% of its total investment exposure to the industrial sector as a whole.</p> <p>(Classification of Industrial sector to be done on the lines of classification in Industries done by CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy)</p> <p>Subject to exposure limits as per Insurance Act, 1938, investment in equity including preference shares, investment in equity convertible part of debentures should not exceed 50% of the above exposure norms. A similar 50% of exposure norms limit would also apply to investment in immovable property.</p>		
-----	---	---	--	--

**CERTIFICATION**

Certified that the information given herein are correct and complete to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed or suppressed.

Date: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_  
Full Name & Designation

"

N. RANGACHARY, Chairman  
[No. ADVT-3/4/Exty/161/2001]

